



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, सितम्बर 12—सितम्बर 18, 2004 शनिवार/भाद्र 21—भाद्र 27, 1926  
No. 38] NEW DELHI, SEPTEMBER 12—SEPTEMBER 18, 2004 SATURDAY/BHADRA 21—BHADRA 27, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )  
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय  
( राजभाषा विभाग )

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा०का०नि० 311.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की अधिसूचना, जो कि भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा०का०नि० 1 दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अनुसूची के अंग्रेजी पाठ में क्रम सं० 3 आशुलिपिक ( श्रेणी-III) पद के स्तंभ संख्या 13 के शीर्षक में, "( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए )" के स्थान पर "( स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए )" पढ़ें।

[संख्या-14034/47/2002-रा.भा. (प्रशिक्षण)]

एस० रमणन, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th September, 2004

**G.S.R. 311.**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, published vide G.S.R. 1 dated the 24th December, 2003, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), in the English version, under serial number 3 of the schedule relating to Stenographer (Grade-III) post, in column number 13, in the heading, “(for considering promotion)” read “(for considering confirmation)”.

[No. 14034/47/2002-OL (Trg.)]

S. RAMANAN, Under Secy.

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )

( केन्द्रीय बायलर बोर्ड )

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

**सा०का०नि० 312.**—भारतीय बायलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए, जिसके प्रस्ताव केन्द्रीय बायलर बोर्ड भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करता है कतिपय विनियमों का निम्नलिखित मसौदा उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर राजपत्र, जिसमें इस अधिसूचना का प्रकाशन सम्मिलित है, को जनता के लिए उपलब्ध कराये जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जायेगा।

2. उक्त मसौदे के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

3. आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, केन्द्रीय बायलर बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को भेजे जा सकते हैं।

## मसौदा विनियम

1. (1) इन विनियमों को भारतीय बायलर (चौथा संशोधन) विनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय बायलर विनियम, 1950 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जायेगा), में विनियम 57 के खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामतः :—

“(ख) अन्य राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वैलड्ड ट्यूबें जो बायलर सुपर हीटर और हीट एक्सचेंजर ट्यूबों के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण प्रायः प्रयोग में लाए जाने के लिए जानी जाती हैं, और जिन्हें विशिष्ट रूप से इन विनियमों द्वारा निषेध नहीं किया गया है, को भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी ट्यूबें इन विनियमों की अपेक्षाओं को पूरी करती हों और इन विनियमों के अनुसार प्रमाणित हों।

बशर्ते यदि ट्यूबों का इन विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित दबाव पर हाइड्रोलिक परीक्षण नहीं किया गया है, जो निरीक्षण प्राधिकारी निर्माता/फैब्रीकेटरों की वर्कशापों अथवा प्रयोगकर्ता के परिसरों में अपेक्षित दबाव पर हाइड्रोलिक परीक्षण देखने के पश्चात् ऐसी ट्यूबों को स्वीकार कर सकता है।”

3. उक्त विनियमों में, 151 विनियम में, खंड (i) में, शुरू के पैराग्राफ में, “सभी बट्ट वेलिड्ड जोड़ों” शब्दों के लिए “बट्ट वेलिड्ड जोड़ों” जैसा कि खंड (ज) में निर्दिष्ट किया गया है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त विनियम में, विनियम 266 में, खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“(छ) मरम्मत के पश्चात् रेडियोग्राफिकल जांच—मरम्मत किए गए सभी क्षेत्र अनुमोदित तकनीकों द्वारा रेडियोग्राफिक या रेडियोस्कोपिक जांच के अध्याधीन होंगे”;

5. उक्त विनियमों में, 365 विनियम में “खण्ड (ख) में, उप खंड (ii) में, मद (2) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामतः :—

“(iii) अनफायरड बॉयलरों के निर्माण में जब डिसड एन्ड गर्म सतह का रूप नहीं लेते हैं तो आई एस : 2825 के अनुरूप कोल्ड स्पन डिसड एन्डस प्रयोग किया जा सकेगा”।

6. उक्त विनियमों में, 382 विनियम में, खंड (क) में, “त्रिपुरा—टी आर” शब्दों के पश्चात् “उत्तरांचल—यू आर” शब्दों को शामिल किया जाएगा।

7. उक्त विनियमों में, 391 (क) विनियम में, खंड (ख) में, उप खंड (ii) में “तकनीकी सलाहकार (बॉयलर)” शब्दों के लिए “मुख्य बॉयलर निरीक्षक” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों में, 561 विनियम में, खंड (ख) में, उप खंड (vii) में, टिप्पण (2) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामतः—

(3) सभी बट्ट वेलिड्ड जोड़ों की रेडियोग्राफिक/रेडियोस्कोपी अथवा अल्ट्रासोनिक परीक्षण मैग्नेटिक पार्टिकल निरीक्षण अथवा लिविड डाई पेनिट्रेंट निरीक्षण जैसी अन्य अनुमोदित विधियों द्वारा अविनाशक जांच की जायेगी। जब वेलिड्ड संघटकों पर रेडियोग्राफी के बदले रेडियोग्राफिक परीक्षण किया जाना होगा तो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात् :—

(1) निरीक्षण प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की जायेगी और उसमें निम्नलिखित शामिल किये जायेंगे :—

- (i) पदार्थ तथा मोटाई रेंज
- (ii) उपकरण योग्यताएं
- (iii) परीक्षण वस्तु विश्लेषण योजना
- (iv) रेडियोस्कोपिक पैरामीटर
- (v) छाया प्रसंस्करण पैरामीटर
- (vi) छाया प्रदर्शन पैरामीटर
- (vii) छाया प्राप्ति अपेक्षाएं
- (viii) स्वीकृति-अस्वीकृति मानदंड कोड संदर्भ
- (ix) कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- (x) आपरेटर की पहचान

(2) रेडियोस्कोपिक छाया की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक इमेज प्रोसेसर की सहायता से प्रणाली को समर्थन दिया जायेगा और प्रणाली कार्य-निष्पादन गुणवत्ता इन्हें दर्शायेगा :—

- (i) 3 की पतला खंड वैषम्य संवेदनशीलता
- (ii) 2 की मोटा खंड वैषम्य संवेदनशीलता
- (iii) प्रति एम एम 3 लाइन जोड़ा का स्थानक विभेदन

- (iv) आई क्यू आई संवेदनशीलता—जब तार के आई क्यू आई का प्रयोग किया जाए तब जोड़ की मोटाई का 2 तार के व्यास धुरी प्रणाली की न्यूनतम संवेदनशीलता की धुरी की ओर उन्मुख होगी।
- (3) प्रतिनिधित्व वाले जोड़ के भाग विशेष के साथ सह-संबद्धिकरण हेतु रेडियोस्कोपों को उचित रूप से चिन्हित किया जायेगा।
- (4) निरीक्षणकारी प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रेडियोस्कोपिक जांच की तारीख के बाद पर्याप्त अवधि के लिए रेडियोस्कोपिक जांच आंकड़ों का निर्माता के संयंत्र में वीडियोटेप, मैग्नेटिक डिस्क अथवा ऑप्टिकल डिस्क में रिकार्ड और भंडारण किया जायेगा। रिकार्ड रिटेंशन अवधि में किसी भी समय दक्ष रेडियोस्कोपिक जांच रिकार्ड प्रत्यावर्तन उपलब्ध कराया जाएगा और यह परीक्षण वस्तु के लिए अनुरेखनीय होगा।
- (5) जब रेडियोस्कोपिक जांच के फलस्वरूप मरम्मत कर दी जाती है तो मरम्मत की कामयाबी का मूल्यांकन करने के लिए उसी रेडियोस्कोपिक तकनीक का प्रयोग करके मरम्मत किये गये भागों की पुनः जांच की जायेगी।
- (6) रेडियोस्कोप जांच संबंधी आंकड़ों की उचित व्याख्या करने में सहायता पहुंचाने के लिए प्रयोग में लायी गयी तकनीक के ब्यौरे आंकड़ों के साथ दिए जायेंगे। कम से कम उक्त सूचना में अनुमोदित प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं और प्रणाली निष्पादन के परीक्षण संबंधी आंकड़े सम्मिलित होंगे।

9. उक्त विनियम में, प्रपत्र 4 में, निम्नलिखित टिप्पण को अंत में शामिल किया जाएगा, नामतः:

“टिप्पण : जहां स्टील का विनिर्माण एक निर्माता द्वारा होता है, जो एक सुप्रसिद्ध स्टील निर्माता के रूप में नहीं जाना जाता, उसका परीक्षण प्रमाण-पत्र निरीक्षक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा”।

[फा. सं. 6(1)/2003-बायलर]

वी. के. गोयल, सचिव, केन्द्रीय बायलर बोर्ड

पाद टिप्पण :—मुख्य विनियमों को का.आ. 600 दिनांक 15 सितम्बर 1950 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा.का.नि. 178 दिनांक 24 मार्च, 1990;
2. सा.का.नि. 179 दिनांक 24 मार्च, 1990;
3. सा.का.नि. 488 दिनांक 9 अक्टूबर, 1993;
4. सा.का.नि. 516 दिनांक 23 अक्टूबर, 1993;
5. सा.का.नि. 634 दिनांक 25 दिसम्बर, 1993;
6. सा.का.नि. 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994 शुद्धिपत्र सा.का.नि. 223 दिनांक 14 मई, 1994;
7. सा.का.नि. 250 दिनांक 4 जून, 1994;
8. सा.का.नि. 402 दिनांक 13 अगस्त, 1994;
9. सा.का.नि. 427 दिनांक 20 अगस्त, 1994;
10. सा.का.नि. 562 दिनांक 12 नवम्बर, 1994;
11. सा.का.नि. 607 दिनांक 10 दिसम्बर, 1994;
12. सा.का.नि. 83 दिनांक 25 फरवरी, 1995;
13. सा.का.नि. 93 दिनांक 4 मार्च, 1995;
14. सा.का.नि. 488 दिनांक 9 नवम्बर, 1996;
15. सा.का.नि. 582 दिनांक 28 दिसम्बर, 1996;
16. सा.का.नि. 59 दिनांक 25 जनवरी, 1997;
17. सा.का.नि. 117 दिनांक 1 मार्च, 1997;

18. सा.का.नि. 172 दिनांक 29 मार्च, 1997;
19. सा.का.नि. 221 दिनांक 21 नवम्बर, 1998;
20. सा.का.नि. 131 दिनांक 1 मई, 1999;
21. सा.का.नि. 139 दिनांक 8 मई, 1999; शुद्धिपत्र सा.का.नि. 201 दिनांक 7 अप्रैल, 2001;
22. सा.का.नि. 237 दिनांक 31 जुलाई, 1999;
23. सा.का.नि. 345 दिनांक 23 अक्टूबर, 1999;
24. सा.का.नि. 397 दिनांक 14 अक्टूबर, 2000;
25. सा.का.नि. 219 दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
26. सा.का.नि. 496 दिनांक 8 सितम्बर, 2001;
27. सा.का.नि. 672 दिनांक 15 दिसम्बर, 2001;
28. सा.का.नि. 201 दिनांक 19 जून, 2004;
29. सा.का.नि. 203 दिनांक 19 जून, 2004;
30. सा.का.नि. 265 दिनांक 7 अगस्त, 2004

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 8th September, 2004

**G.S.R. 312.**—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published, as required by Sub-section (1) of Section 31 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date the Gazette containing the publication of this notification is made available to the public.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board.

3. Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

### DRAFT REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Fourth Amendment) Regulations, 2004.
- (2) They shall come into force after final publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 57, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) The welded tubes conforming to other national or international standard which are known to be commonly used as being suitable for use as boiler, superheater or heat exchanger tubes and not specifically prohibited by these regulations can also be used provided such tubes satisfy the requirements of these regulations and are certified as per these regulations :

Provided that if the tubes are not hydraulically tested at the pressure required under this regulations, the Inspecting Authority may accept such tubes after witnessing hydraulic test at the required pressure at the maker's/fabricator's works or user's premises”;

3. In the said regulations, in regulation 151, in clause (i), in the opening paragraph, for the words “All butt welded joints”, the words “Butt welded joints as indicated in clause (h)” shall be substituted.

4. In the said regulations, in regulation 266, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :

“(g) Radiographical Examination after Repairs—All repaired areas shall be subjected to Radiographic or Radioscopic Examination by the approved techniques.”;

5. In the said regulations, in regulation 365 “in clause (b), in sub-clause (2), after item (ii), the following shall be inserted, namely :

“(iii) In the construction of unfired boilers when the dished ends do not form of the heating surface, cold spun dished ends conforming to IS : 2825 may be used.”

6. In the said regulations, in regulation 382, in clause (a), after the words “Tripura ..... TR”, the words “Uttaranchal ..... UR” shall be inserted.

7. In the said regulations, in regulation 391A, in clause (b), in sub-clause (ii), for the words, “Technical Adviser (Boilers)”, the words, “Chief Inspector of Boilers” shall be substituted.

8. In the said regulations, in regulation 561, in clause (b), in sub-clause (viii), after Note (2), the following shall be inserted, namely :

“(3) All butt welded joints shall be subjected to non-destructive examination by radiographic, radioscopy or other approved methods such as ultrasonic testing, magnetic particle inspection or liquid dye penetrant inspection. When radioscopy examination is to be performed in lieu of radiography on welded components, the following requirements shall be met, namely :—

- (1) A written procedure shall be submitted for approval to the Inspecting Authority which shall contain the following :—
  - (i) material and the thickness range;
  - (ii) equipment qualifications;
  - (iii) test object scan plan;
  - (iv) radioscopy parameters;
  - (v) image processing parameters;
  - (vi) image display parameters;
  - (vii) image archiving requirements;
  - (viii) accept-reject criteria (Code reference);
  - (ix) performance evaluation;
  - (x) operator identification.
- (2) The system shall be aided with an image processor to enhance the quality of the radioscopy images and system performance quality shall exhibit—
  - (i) a thin section contrast sensitivity of 3%;
  - (ii) a thick section contrast sensitivity of 2%;
  - (iii) a spatial resolution of 3 line pairs per mm;
  - (iv) IQI sensitivity—2% of the joint thickness when wire IQI's are to be used, the wire diameter axis shall be oriented along the axis of the least sensitivity of the system.
- (3) Radioscopes are to be properly marked to co-relate with particular part of joint represented.
- (4) The radioscopy examination data shall be recorded and stored on videotape, magnetic disk or optical disk at the maker's plant for a sufficient period after the date of radioscopy examination as specified by the Inspecting Authority, efficient radioscopy examination record recall shall be made available at any time over the record retention period and shall be traceable to the test objects.
- (5) When repair has been performed as a result of radioscopy examination, the repaired areas shall be re-examined using the same radioscopy technique to evaluate the effectiveness of the repair.

- (6) To aid in proper interpretation of the radioscopic examination data, the details of the technique used shall accompany the data. As a minimum, the information shall include the approved procedure requirements and system performance test data.”;

9. In the said regulation, in Form IV, the following Note shall be inserted at the end, namely :—

“Note : Where the steel is manufactured by a maker, who is not recognised as a well known Steel Maker, the certificate of test shall be signed by the Inspecting Authority.”

[F. No. 6(1)/2003-Boilers]

V. K. GOEL, Secy., Central Boilers Board

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* S.O. 600, dated the 15th September, 1950 and subsequently amended *vide* notifications :—

- (i) G.S.R. 178, dated the 24th March, 1990;
- (ii) G.S.R. 179, dated the 24th March, 1990;
- (iii) G.S.R. 488, dated the 9th October, 1993;
- (iv) G.S.R. 516, dated the 23rd October, 1993;
- (v) G.S.R. 634, dated the 25th December, 1993;
- (vi) G.S.R. 107, dated the 26th February, 1994; Errata G.S.R. 223, dated the 14th May, 1994;
- (vii) G.S.R. 250, dated the 4th June, 1994;
- (viii) G.S.R. 402, dated the 13th August, 1994;
- (ix) G.S.R. 427, dated the 20th August, 1994;
- (x) G.S.R. 562, dated the 12th November, 1994;
- (xi) G.S.R. 607, dated the 10th December, 1994;
- (xii) G.S.R. 83, dated the 25th February, 1995;
- (xiii) G.S.R. 93, dated the 4th March, 1995;
- (xiv) G.S.R. 488, dated the 9th November, 1996;
- (xv) G.S.R. 582, dated the 28th December, 1996;
- (xvi) G.S.R. 59, dated the 25th January, 1997;
- (xvii) G.S.R. 117, dated the 1st March, 1997;
- (xviii) G.S.R. 172, dated the 29th March, 1997;
- (xix) G.S.R. 221, dated the 21st November, 1998;
- (xx) G.S.R. 131, dated 1st May, 1999;
- (xxi) G.S.R. 139, dated the 8th May, 1999; Errata G.S.R. 201, dated 7th April, 2001;
- (xxii) G.S.R. 237, dated 31st July, 1999;
- (xxiii) G.S.R. 345, dated 23rd October, 1999;
- (xxiv) G.S.R. 397, dated 14th October, 2000;
- (xxv) G.S.R. 219, dated 14th April, 2001;
- (xxvi) G.S.R. 496, dated 8th September, 2001;
- (xxvii) G.S.R. 672, dated 15th December, 2001;
- (xxviii) G.S.R. 127, dated 13th April, 2002;
- (xxix) G.S.R. 407, dated 22nd November, 2003;
- (xxx) G.S.R. 201, dated 19th June, 2004;
- (xxxi) G.S.R. 203, dated 19th June, 2004;
- (xxxii) G.S.R. 265, dated 7th August, 2004.

## रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 313.—केन्द्रीय सरकार, रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल संरक्षण बल नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2004 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रेल संरक्षण बल नियम, 1987 के अध्याय 2 में, "रेल संरक्षण विशेष बल" शीर्ष के अधीन पैरा 7 के सामने प्रविष्टियों के नीचे निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"7.6 बटालियनों में आर्मरों जैसे प्रशिक्षित वायरलेस कार्मिक होंगे। ये पद कांडर बाह्य पद होंगे। पदों की संख्या वह होगी जो समय-समय पर विनिश्चित की जाए। ये पद इस संबंध में समय-समय पर महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल द्वारा जारी किए गए निदेशों द्वारा शासित होंगे।"
3. रेल संरक्षण बल नियम, 1987 की अनुसूची 1 में मद II के अधीन निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"39. निरीक्षक/वायरलेस  
40. उपनिरीक्षक/वायरलेस  
41. सहायक उपनिरीक्षक/वायरलेस  
42. हेड कांस्टेबल/वायरलेस  
43. कांस्टेबल/वायरलेस"

[फा. सं. 2003/सेक(स्पे)/6/13]

वी. एन. माथुर, सचिव (रेलवे बोर्ड) पदेन अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 951(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1987 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

क्र. सं.	सा.का.नि.	तारीख
1.	374	24-07-1992
2.	564	07-11-1994
3.	164	20-03-1995
4.	45	12-01-1996
5.	39(अ)	17-01-1996
6.	45(अ)	29-01-1997
7.	151(अ)	11-03-1997
8.	229	15-07-1999
9.	756(अ)	02-11-1999
10.	768(अ)	12-11-1999
11.	286	20-07-2000
12.	359	08-09-2000
13.	483	24-08-2001
14.	790(अ)	22-10-2001
15.	618	12-11-2001
16.	257(अ)	28-03-2003
17.	448(अ)	29-05-2003
18.	312(अ)	13-05-2004
19.	591(अ)	17-05-2004
20.	592(अ)	17-05-2004
21.	593(अ)	17-05-2004



## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 25th August, 2004

**G.S.R. 313.**—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Protection Force (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Protection Force Rules, 1987, in Chapter II, under heading “Railway Protection Special Force”, below the entries against para 7, the following shall be inserted at the end, namely :—

“7.6 Battalions will have trained wireless personnel like Armourers. These posts will be ex-cadre. The number of posts will be as decided from time to time. These posts will be governed by the Directives issued in this regard by DG/RPF from time to time.”

3. In the Railway Protection Force Rules, 1987 in Schedule I, under item II, the following shall be inserted at the end, namely :—

“39. Inspector/Wireless

40. Sub-Inspector/Wireless

41. Asstt. Sub-Inspector/Wireless

42. Head Constable/Wireless

43. Constable/Wireless”.

[F. No. 2003/Sec (Spl)/6/13]

V.N. MATHUR, Secy. (Railway Board) and Ex-Officio Addl. Secy.

**Foot Note :** The Principal rules were published vide number G.S.R. 951(E) dated the 3rd December, 1987 and subsequently amended vide :—

S. No.	G.S.R.	Date
1.	374	24-07-1992
2.	574	07-11-1994
3.	164	20-03-1995
4.	45	12-01-1996
5.	39(E)	17-01-1996
6.	45(E)	29-01-1997
7.	151(E)	11-03-1997
8.	229	15-07-1999
9.	756(E)	02-11-1999
10.	768(E)	12-11-1999
11.	286	20-07-2000
12.	359	08-09-2000
13.	483	24-08-2001
14.	790(E)	22-10-2001
15.	618	12-11-2001
16.	257(E)	28-03-2003
17.	448(E)	29-05-2003
18.	312(E)	13-05-2004
19.	591(E)	17-05-2004
20.	592(E)	17-05-2004
21.	593(E)	17-05-2004

कृषि मंत्रालय

( कृषि और सहकारिता विभाग )

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2004

**सां.का.नि. 314.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे

27/6 GE/2004 -3

अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन में ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसूचित	12000-375-16500 रु.	चयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 5 वर्ष तक की जा सकती है।)	लागू नहीं होता	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में विशिष्टता सहित एम.एस.सी. मृदा विज्ञान या एम. एस. सी. कृषि रसायन शास्त्र या समतुल्य।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष

(6)

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)

(ii) मृदा सर्वेक्षण कार्य में कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है।

**वांछनीय :** हवाई फोटो का निर्वचन करने या सर्वेक्षण सहित मृदा संरक्षण की किसी अन्य शाखा में योजना और अनुरक्षण में अनुभव या उच्च प्रशिक्षण।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी, या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है), दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

**प्रोन्नति :**

ऐसे मृदा सर्वेक्षण अधिकारी जिन्होंने 10000-15200 रुपए के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक (पात्रता) सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक (पात्रता) सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक (पात्रता) सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

**प्रतिनियुक्ति** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :—

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और अन्य स्वशासी संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(12)

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 10000-15200 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष तक सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) की संरचना :—

- |  |          |
|--|----------|
| (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग                | —अध्यक्ष |
| (ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन)                            | —सदस्य   |
| (iii) संबंधित प्रभाग का संयुक्त सचिव                   | —सदस्य   |
| (iv) प्रभाग का तकनीकी प्रधान                           | —सदस्य   |
| (v) अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण का प्रधान | —सदस्य   |

इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध का शिथिल या संशोधन और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) की संरचना :—

- |  |          |
|--|----------|
| (i) संबंधित प्रभाग का संयुक्त सचिव                       | —अध्यक्ष |
| (ii) प्रभाग का तकनीकी प्रधान                             | —सदस्य   |
| (iii) अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण का प्रधान | —सदस्य   |

[फा. सं. 2-7/2002-एन.आर.एम. III]

एम. पी. थामस, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 19th August, 2004

**G.S.R. 314.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organization (Senior Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Soil Survey Officer in the All India Soil and Land Use Survey Organization under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Soil and Land Use Survey Organization (Senior Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Soil Survey Officer	1 (2004)* *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rule, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	<b>Essential :</b> (i) M.Sc. in Soil Science or M.Sc. in Agriculture Chemistry with specialization in Soil Science from a recognized University or equivalent. (ii) Atleast ten year's experience in Soil survey work.		Age : No Educational qualifications : Yes		One year for direct recruits

**Note 1. :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2. :** The qualification(s) regarding experience is (are) relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Desirable :**

Experience or advanced training in Aerial Photo-interpretation or any other branch of soil conservation including survey, planning and monitoring.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/absorption to be made.
11	12
Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion :</b> Soil Survey Officers in scale of pay of Rs. 10,000—15,200 with 5 years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :—</b>Where juniors who have completed their qualifying (eligibility) service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying (eligibility) service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying (eligibility) service.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract) :</b> Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Agricultural Universities, Indian Council of Agricultural Research and other autonomous institutions.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.</p>

12

[The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.]

If a Departmental Promotion Committee exists. What is its composition?

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—**

- |   |           |
|---|-----------|
| (1) Chairman or Member of Union Public Service Commission | —Chairman |
| (2) Joint Secretary (Administration)                      | —Member   |
| (3) Joint Secretary of the Division concerned             | —Member   |
| (4) Technical Head of the Division                        | —Member   |
| (5) Head of the All India Soil and Land Use Survey        | —Member   |

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—**

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) Joint Secretary of the Division concerned      | —Chairman |
| (2) Technical Head of the Division                 | —Member   |
| (3) Head of the All India Soil and Land Use Survey | —Member   |

[F. No. 2-7/2002-NRM.III]

M.P. THOMAS, Under Secy.

( पशुपालन और डेयरी विभाग )

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 315.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) में केयरटेकर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन और डेयरी विभाग (केयरटेकर) भर्ती नियम, 2004 है।  
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
केयरटेकर	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100- 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	7	8		9	10
	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी			
	11			12	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा।		प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार की निम्नलिखित श्रेणियों अथवा अधिकारियों में से वे जो हाउस कीपिंग से जुड़े कार्यों में अनुभव रखते हों, अर्थात् :— (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक तथा पशुपालन और डेयरी विभाग के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे उच्च श्रेणी लिपिक। (2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी लिपिक तथा पशुपालन और डेयरी विभाग के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने संबंधित ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। आमेलन—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हों और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और हाउस कीपिंग तथा सुरक्षा का अनुभव हो :			



1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

2. भवनों/कार्यालयों की स्वच्छता और रखरखाव/केयरटेकिंग का अनुभव तथा योग्यता।

(ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा गया समझा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा पर आमेलित कर लिया जाएगा)।

**टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

लागू नहीं होता

- |   |          |
|---|----------|
| 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)                   | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव (प्रशासन)                         | —सदस्य   |
| 3. अवर सचिव (वित्त)                           | —सदस्य   |
| 4. प्रशासन अनुभाग 2 का प्रभारी अनुभाग अधिकारी | —सदस्य   |

[फा. सं. ए.-12018/4/2003-प्रशासन-1]

पी. एल. मीना, अवर सचिव

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 3rd September, 2004

**G.S.R.** —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Caretaker in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying) namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry and Dairying (Caretaker) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, its classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

**4. Disqualification.**—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

2716 GT/2004-5

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Non-selection or Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1977
1	2	3	4	5	6
Caretaker	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7		8	9		10
Not applicable		Not applicable	Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
By deputation (including short-term contract)/absorption		<b>Deputation :</b> From amongst the following categories or officers of Central Government having experience in duties relating to House Keeping, namely :— (i) Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service and Upper Division Clerks working in subordinate offices under the control of the Department of Animal Husbandry and Dairying; (ii) Lower Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service and Lower Division Clerks working in subordinate offices under the control of the Department of Animal Husbandry and Dairying with eight years regular service in the respective grade. <b>Absorption :</b> Armed Forces Personnel due to retire or to be transferred to reserve, within a period of one year and possessing following qualifications			

and experience of House Keeping and Security shall also be considered :

1. Matriculation or equivalent from a recognized Board/University or equivalent.
2. Experience and aptitude in sanitation and maintenance/caretaking of buildings/offices. (Such persons would be treated as on deputation up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they would be absorbed on transfer/short-term contract).

Note :—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—**

Not applicable.

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Director/Deputy Secretary (Administration)             | —Chairman |
| 2. Under Secretary (Administration)                       | —Member   |
| 3. Under Secretary (Finance)                              | —Member   |
| 4. Section Officer in charge of Administration II Section | —Member   |

[F. No. A-12018/4/2003-Admn. I]

P. L. MEENA, Under Secy.

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 316.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 212 दिनांक 11 जून, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (i) दिनांक 19 जून, 2004 में इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से भारत के जिस राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित हुई हो उसकी प्रतियां आम जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि समाप्त होने तक आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, आम जनता को उक्त राजपत्र की प्रतियां 20 जून, 2004 को उपलब्ध करवायी गयी थीं;

और जबकि, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाएगा।

(2) वे 01 अक्टूबर, 2004 से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली में, नियम 51 के वर्तमान मूल पाठ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“51. अंशदान की दर—किसी मजदूरी अवधि के लिए अंशदान की राशि निम्नलिखित के संबंध में होगी :—

- (क) नियोक्ता का अंशदान, किसी कर्मचारी को देय मजदूरी के 4¼ प्रतिशत के बराबर राशि (अगले रुपये तक पूर्णांकित की गयी); और
- (ख) कर्मचारी का अंशदान, किसी कर्मचारी को देय मजदूरी के 1¼ प्रतिशत के बराबर राशि (अगले रुपये तक पूर्णांकित की गयी)।”

पाद टिप्पणी : मूल नियमों को भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 22-6-1950 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. सा.का.नि. संख्या 80 दिनांक 9-1-1960
2. सा.का.नि. संख्या 1200 दिनांक 27-9-1960
3. सा.का.नि. संख्या 594 दिनांक 29-3-1963
4. सा.का.नि. संख्या 240 दिनांक 6-2-1964
5. सा.का.नि. संख्या 1834 दिनांक 18-12-1964
6. सा.का.नि. संख्या 474 दिनांक 19-3-1965
7. सा.का.नि. संख्या 1082 दिनांक 29-6-1966
8. सा.का.नि. संख्या 545 दिनांक 14-4-1967
9. सा.का.नि. संख्या 500 दिनांक 6-3-1968
10. सा.का.नि. संख्या 677 दिनांक 29-3-1968
11. सा.का.नि. संख्या 1106 दिनांक 22-5-1968
12. सा.का.नि. संख्या 2113 दिनांक 28-11-1968
13. सा.का.नि. संख्या 306 दिनांक 7-3-1974
14. सा.का.नि. संख्या 1122 दिनांक 1-10-1974
15. सा.का.नि. संख्या 56 दिनांक 23-12-1976
16. सा.का.नि. संख्या 60 दिनांक 5-1-1982
17. सा.का.नि. संख्या 129 दिनांक 9-2-1987
18. सा.का.नि. संख्या 199 दिनांक 6-3-1990
19. सा.का.नि. संख्या 76 दिनांक 22-1-1991
20. सा.का.नि. संख्या 368 दिनांक 27-3-1992
21. सा.का.नि. संख्या 522 दिनांक 16-11-1996
22. सा.का.नि. संख्या 582 (अ) दिनांक 23-12-1996
23. सा.का.नि. संख्या 225 दिनांक 21-4-1997
24. सा.का.नि. संख्या 226 दिनांक 22-4-1997

25. सा.का.नि. संख्या 185 दिनांक 1-9-1998
26. सा.का.नि. संख्या 129 दिनांक 8-4-2000
27. सा.का.नि. संख्या 210 दिनांक 27-3-2001
28. सा.का.नि. संख्या 28 दिनांक 2-1-2004
29. सा.का.नि. संख्या 172 (अ) दिनांक 4-3-2004

[सं. एस-38012/1/2003-एस.एस.-1]

संयुक्ता राय, अवर सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

New Delhi, the 26th August, 2004

**G.S.R. 316.**—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published, as required under Sub-section (i) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. GSR 212 dated the 11th June, 2004 in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i) dated the 19th June, 2004 for inviting objections or suggestions from any persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of fortyfive days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 20th June, 2004.

And whereas, objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Government.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely :—

1. (a) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (1st Amendment) Rules, 2004.

(b) They shall come into force with effect of from 1st October, 2004.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, the present text of Rule 51 shall be substituted by the following :—

“51. Rate of Contribution—The amount of contribution for a wage period shall be in respect of—

- (a) employer's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to four and three fourth per cent of the wages payable to an employee; and
- (b) employer's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to one and three fourth per cent of the wages payable to an employee”.

**Foot Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i) *vide* Government of India, Ministry of Labour Notification No. SRO 212 dated 22-6-1950 and subsequently amended by the following notifications :—

1. GSR No. 80 dated 9-1-1960
2. GSR No. 1200 dated 27-9-1960
3. GSR No. 594 dated 29-3-1963
4. GSR No. 240 dated 6-2-1964
5. GSR No. 1834 dated 18-12-1964
6. GSR No. 474 dated 19-3-1965

27/8 9/2004-5

7. GSR No. 1082 dated 29-6-1966
8. GSR No. 545 dated 14-4-1967
9. GSR No. 500 dated 6-3-1968
10. GSR No. 677 dated 29-3-1968
11. GSR No. 1106 dated 22-5-1968
12. GSR No. 2113 dated 28-11-1968
13. GSR No. 306 dated 7-3-1974
14. GSR No. 1122 dated 1-10-1974
15. GSR No. 56 dated 23-12-1976
16. GSR No. 60 dated 5-1-1982
17. GSR No. 129 dated 9-2-1987
18. GSR No. 199 dated 6-3-1990
19. GSR No. 76 dated 22-1-1991
20. GSR No. 368 dated 27-3-1992
21. GSR No. 522 dated 16-11-1996
22. GSR No. 582(E) dated 23-12-1996
23. GSR No. 225 dated 21-4-1997
24. GSR No. 226 dated 22-4-1997
25. GSR No. 185 dated 1-9-1998
26. GSR No. 129 dated 8-4-2000
27. GSR No. 210 dated 27-3-2001
28. GSR No. 28 dated 2-1-2004
29. GSR No. 172(E) dated 4-3-2004

[No. S-38012/1/2003-S.S. -I.]

SANJUKTA RAY, Under Secy.